इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये
(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 5 अंक सं. : 9 अप्रैल, 2013

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूची

मौदेकि नीति की समीक्षा----------1
मुख्य घटनाएं----------2
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां----------2
बैंकिंग ागत की घटनाएं---------- 2
विनियामकों के कथन ----------4
बीमा ----------5
विदेशी मुद्रा ----------6
उत्पाद एवं गठजोड़----------6
नयी नियुक्तियां----------6
अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक---------- 6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं- ----------7
शब्दावली ----------7
संस्थान की गतिविधियां ----------7
संस्थान समाार----------7
बाज़ार की खबरें----------8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूाना / समाार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के िलए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

नीति की मध्य तिमाही समीक्षा - 19 मार्च 2013

मौद्रिक एवं चलनिधि सम्बन्धी उपाय

चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत नीतिगत पुनर्खरीद (Repo) दर तात्कालिक प्रभाव से 7.75% से 25 आधार अंक घटा कर 7.5% कर दी गई।

फलत: चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत प्रति-पुनर्खरीद (reverse repo) दर 6.5% पर समायोजित की गई है और सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर और बैंक दर तात्कालिक प्रभाव से 8.5% कर दी गई है।

वृद्धि

वर्ष 2012-13 की 3री तिमाही में 4.5% की दर पर भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि पिछली 15 तिमाहियों में सबसे कमजोर रही। अब तक की समग्र वृद्धि के मुख्य आधार सेवा क्षेत्र की वृद्धि भी घट कर किसी दशक के सर्वाधिक धीमे स्तर पर पहुंच गई। जहां समग्र औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि ने जनवरी में सकारात्मक रुख अपनाया, वहीं पूंजीगत माल के उत्पादन और खनन गतिविधि में संकुचन की प्रवृत्ति जारी रही। फरवरी में व्यापक रूप से सेवाओं में धीमे विस्तार का निरूपण करते हुए क्रय प्रबन्धकों के मिश्रित सूचकांक में गिरावट आ गई। कृषि क्षेत्र में खरीफ उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमानों में पिछले वर्ष के स्तर के मुकाबले गिरावट के संकेत प्राप्त होते हैं। हालांकि, उसकी रबी के उत्पादन से कम से कम आंशिक रूप से भरपाई हो सकती है, जिसकी बुवाई संतोषजनक रही है।

मुद्रास्फीति

सुर्खियों में आई वर्षानुवर्ष थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति आवश्यक रूप से पेट्रोलियम उत्पादों की नियंत्रित कीमतों में किए गए ऊर्ध्वमुखी संशोधन का निरूपण करते हुए जनवरी में 6.6% से बढ़कर फरवरी 2013 में 6.8% तक पहुंच गई। दूसरी ओर, खाद्येतर विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति और उसकी गति का धातुओं, कपड़ों एवं रबड़ उत्पादों की कीमतों में कमी से बल पा कर उस प्रक्षेप वक्र से गिरने का क्रम जारी रहा जो सितम्बर, 2012 में आरंभ हुआ था। चिंताजनक रूप से, नये संयोजित (ग्रामीण और शहरी) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार : 2010 = 100) की मुद्रास्फीति के फरवरी 2013 में 10.9% के उच्च स्तर पर रहने के परिणामस्वरूप खाद्य मदों, विशेषत: अनाजों और

प्रोटीनों से मूल्य सम्बन्धी निरंतर दबावों के आधार पर खुदरा मुद्रास्फीति के उस ऊर्ध्वमुखी राह पर जाने का

क्रम जारी रहा, जो अक्तूबर, 2012 में नियत हुई थी। फलत: वर्ष के दौरान थोक और उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति के बीच अपविन्दुता के व्यापक होते जाने का क्रम जारी रहा।

मौद्रिक एवं चलनिधि की स्थितियां

मुद्रा आपूर्ति (एम3) और बैंक ऋण वृद्धि व्यापक रूप से उनके संशोधित संकेतात्मक प्रक्षेप वक्र के संरेखण में रही। भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सरकार के नकदी शेषों के सामान्य से उच्चतर स्तर पर बने रहने के परिणामस्वरूप चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत बैंकों द्वारा निवल आहरणों द्वारा यथा-निरूपित चलनिधि की कमी संकेतात्मक सहूलियत के स्तर से अधिक पर बनी रही। 9 फरवरी से प्रभावी बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) में 25 आधार अंकों की कमी और फरवरी से 200 बिलियन रुपये की खुले बाज़ार की खरीदियों ने मुद्रा बाज़ार की दरों को नीतिगत पुनर्खरीद (Repo) दर से सम्बद्ध बनी रहने में समर्थ बनाया। रिज़र्व बैंक खुले बाज़ार के परिचालनों (OMOs) सहित विविध साधनों के माध्यम से चलनिधि का सक्रिय रूप से प्रबन्धन करना जारी रखेगा, ताकि अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को ऋण के पर्याप्त प्रवाह को जारी रखा जा सके।

मुख्य घटनाएं

पूर्णत: महिला बैंक नवम्बर से परिचालित होगा

वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने घोषणा की है कि भारत का पूर्णत: महिला बैंक पूरे देश में फैली छ: शाखाओं के माध्यम से इस वर्ष नवम्बर से परिचालन आरंभ कर देगा। योजना यह है कि इसकी शुरूआत देश के प्रत्येक महत्वपूर्ण क्षेत्र, अर्थात दक्षिण, पूर्व, मध्य, उत्तर और उत्तर-पूर्व में कम से कम एक शाखा से की जाए।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

विदेशी बैंक शाखाएं स्थानीय संस्था में रूपांतरित होंगी

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारत में प्रवेश करने वाले विदेशी बैंकों से उस एक खण्ड पर सहमति व्यक्त करने हेतु कहा जा रहा है, जिसमें इन बैंकों के लिए घरेलू निगमन अनिवार्य बना दिए जाने पर उनसे उनकी शाखा के परिचालनों को पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक कम्पनी (WOS) के रूप में रूपांतरित करना अपेक्षित है। माना जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस शर्त को किसी नये विदेशी बैंक के प्रवेश के समय शामिल करेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बात पर बल दिया है कि वित्तीय स्थिरता वाले पि

रप्रेक्ष्य से प्रवेश के स्तर पर ही सहायक कम्पनी वाले रूप में उपस्थिति को अनिवार्य करने की आवश्यकता होगी। इसीप्रकार, शाखाएं स्थापित करने वाले नये प्रवेशकर्ताओं के लिए यह अनिवार्य

होगा कि वे अपने तुलनपत्र के आकार की दृष्टि से सर्वांगी महत्वपूर्ण हो ाने पर पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक कम्पनी (WOS) के रूप में रूपांतरित हो ाएं।

बैंक लाइसेंसों की दौड़ में वित्तीय कम्पनियां सबसे आगे

जे.पी. मोरगन की रिपोर्ट के अनुसार नये बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने हेतु बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा प्रवर्तित गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को अग्रिम पंक्ति के धावकों के रूप में देखा जा रहा है। एल एण्ड टी फाइनैन्स, बजाज फिनसर्व, एम एण्ड एम फाइनैन्सियल और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनैन्स जैसी कम्पनियां एकल आधार वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की तुलना में लाभजनक स्थिति में हैं । भारतीय रिज़र्व बैंक के नये दिशानिर्देशों के अनुसार निजी क्षेत्र की कम्पनियां अथवा समूह और गैर-बैंकिंग कम्पनियां एक पूर्णत: स्वाधिकृत गैर-परिचालित वित्तीय नियंत्रक कम्पनी (NOFHC) के माध्यम से बैंक गठित करने की पात्र होंगी। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आगामी 12 महीनों की अवधि में केवल 4-5 लाइसेंस जारी किए जाने की आशा है। उसे विलयन और अभिग्रहण के अवसरों के साथ ही मुख्य जमाराशियों और उनके साथ ही साथ प्रतिभा को बढ़ाने के लिए पर्याप्त रूप से प्रतिस्पर्धा की आशा है।

सभी बैंक शाखाएं क्षतिग्रस्त नोट बदलेंगी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से (सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सभी बैंक शाखाओं में गंदे नोटों के अलावा कटे और कटे-फटे बैंकनोटों को बदले जाने और अच्छी गुणवत्ता वाले स्वच्छ बैंकनोटों / सिक्कों को जारी किए जाने हेतु सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कहा है। यह सुविधा किसी भेदभाव के बिना जनता के सभी सदस्यों को सभी कार्य-दिवसों को प्रदान की जानी चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को प्रोत्साहन

इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को गति प्रदान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से ऐसे स्थानों पर, जहां इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली (ECS) उपलब्ध हो उत्तर-दिनांकित चेकों (PDCs) और समीकृत मासिक किस्त भुगतान के चेक न स्वीकार करने के लिए कहा है। इसप्रकार नये उधारकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा प्रणाली की सुविधा के उपलब्ध होने पर अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली अपनानी पड़ेगी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से उधारकर्ताओं से नये अधिदेश प्राप्त करके मौजूदा उत्तर-दिनांकित चेकों (PDCs) को इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा प्रणाली में रूपांतरित करने हेतु सभी प्रकार के प्रयास करने हेतु भी कहा है।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

5

कार्डों की सहायता से वैश्विक लेनदेनों की सीमा निर्धारित करें

धोखाधड़ियों को रोकने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से क्रेडिट और डेबिट कार्डों पर अंतरराष्ट्रीय लेनदेनों की मौद्रिक सीमा निर्धारित करने और जब तक कि ग्राहक द्वारा विशिष्ट रूप से मांग न की जाए वैश्विक पहुंच वाले कार्ड जारी करने से विरत रहने हेतु कहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक का कहना है कि "30 जून तक बैंकों द्वारा जारी सभी चुंबकीय पट्टी वाले सक्रिय कार्डों में ग्राहक की जोखिम प्रोफाइल के आधार पर अंतरराष्ट्रीय उपयोग की प्रारंभिक सीमा तय कर दी जानी चाहिए और वह ग्राहक द्वारा स्वीकार की जानी चाहिए। इसके अलावा, जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, सभी डेबिट कार्डों और ऐसे सभी क्रेडिट कार्डों के लिए जिनका उपयोग अतीत में अंतरराष्ट्रीय लेनदेनों के लिए न किया गया हो, 500 डालर से अनधिक वाली एक प्रारंभिक सीमा लागू की जानी चाहिए।"

ऋण वृद्धि भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमानों से अधिक, जमाराशियों में कमी

भारतीय रिज़र्व बैंक के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार बैंक जमाराशियां 12.73% की मंद दर से बढ़ीं, जबकि 22 फरवरी तक ऋणों में वर्षानुवर्ष आधार पर 16.25% की वृद्धि दर्ज हुई। पखवाड़े के दौरान बैंकों ने लगभग 26,000 करोड़ रुपये के नये ऋण संवितरित किए, जबकि जमारा शियों में उन्हें लगभग 10,000 करोड़ रुपये की हानि हुई। केन्द्रीय बैंक ने इस वित्तीय वर्ष के लिए 16% की ऋण वृद्धि और 15% की जमा वृद्धि का पूर्वानुमान व्यक्त किया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मानदंड कठोर बनाए

ग्राहकों द्वारा वैकल्पिक भुगतान चैनलों का उपयोग किए जाने के परिणामस्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक ने कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेनों के सुरक्षा और जोखिम न्यूनीकरण उपायों को कठोर बना दिया है। तदनुसार, नये डेबिट और क्रेडिट कार्ड ाब तक कि ग्राहक द्वारा अंतरराष्टीय उपयोग की मांग विशिष्ट रूप से न की गई हो, आवश्यक रूप से केवल घरेलू उपयोग के लिए ही ाारी किए ाने ाहिए। वैसे समर्थकारी अंतरराष्ट्रीय उपयोग आवश्यक रूप से यूरोपे, मास्टर कार्ड और वीसा (EMV) चिप और पिन समर्थित होने चाहिए। बैंकों से उन ग्राहकों के लिए जिन्होंने अपने कार्डों का उपयोग कम से कम एक बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया हो, सभी चुंबकीय पट्टी वाले मौजूदा कार्डों को यूरोपे, मास्टर कार्ड और वीसा (EMV) चिप कार्ड में परिवर्तित करने हेतु भी कहा गया है।

विश्वसनीय राजकोषीय समेकन योजनाओं की आवश्यकता

4 मार्च, 2013 को जारी मुद्रा एवं वित्त 2009-12 पर भारतीय रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार एक उपयुक्त राकोषीय-मौद्रिक संमिश्र सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीय राकोषीय समेकन योाना और समन्वय की रणनीतियां तैयार किए ाने की आवश्यकता है। इससे वृद्धि के लक्ष्य और स्थूल-आर्थिक ध्येयों के निराकरण हेतु मौद्रिक नीति के लिए अधिक ऊंाई की प्राप्ति सुगम हो सकेगी। हाल के संकट, ासिसे वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने में स्थूल-आर्थिक स्थिरता की अपर्याप्तता
को रेखांकित हुई है, से राजकोषीय-मौद्रिक समन्वय के लिए कुछेक मूल्यवान नसीहतें सामने आई हैं । अतएव वृद्धि और मूल्य स्थिरता के अलावा वित्तीय स्थिरता को केन्द्रीय बैंकों के लिए एक अलग नी तिगत उद्देश्य का महत्व प्राप्त हुआ है।

मूलभूत सुविधा क्षेत्र के प्रति बैंकों के ऋण जोखिम को लेकर भारतीय रिज़र्व बैंक अतिरिक्त रूप से सतर्क

भारतीय रिज़र्व बैंक मूलभूत सुविधा क्षेत्र के प्रति ऋणदाताओं के ऋण जोखिम (Exposure) के सम्बन्ध में विस्तृत सूाना मंगवा रहा है - ाो एक ऐसा उपाय है ासिका उद्देश्य समस्यामूलक ऋणों में कमी लाना है। बताया ाता है कि विनियामक ने यह सूाना बैंकों के अपने वार्षिक निरीक्षण के एक अंग के रूप में मंगवाई है। अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बिजली जैसे क्षेत्रों के प्रति भारी ऋण जोखिम रखने वाले कतिपय औद्योगिक समूहों में बढ़ते कारपोरेट उत्तोलन (Leverage) के समय -पूर्व संकेतों का उल्लेख किया था। इसके अनुवर्तन में विनियामक प्रणाली के स्तर पर संभाव्य दबाव का आकलन करने का प्रयास कर रहा है। मूलभूत सुविधा क्षेत्र को वाणिज्यिक बैंकों के उधार में वर्षानुवर्ष 16% की वृद्धि हुई, जो दिसम्बर, 2012 के अंत में 6,925 करोड़ रुपये हो गया। इस अवधि में बिाली क्षेत्र को उधार में 22.8% की वृद्धि हुई और वह 3,874 करोड़ रुपये रहा।

महिलाओं के बैंक के सम्बन्ध में रूपरेखा हेतु वित्त मंत्री का पैनल

वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने 1,000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी के साथ महिला बैंक की रूपरे खा तैयार करने हेतु अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को एक 6 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। इस स मिति की अध्यक्षता केनरा बैंक के भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री एम.बी.एन. राव करेंगे और इसमें तीन महिला सदस्यों, यथा - सेवा बैंक की प्रबन्ध निदेशक सुश्री जयश्री व्यास, एसबीआई कैप्स की प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुश्री अरुन्धती भट्टाचार्य और पंजाब नैशनल बैंक की कार्यपालक निदेशक सुश्री उषा अनंतसुब्रह्मण्यम का समावेश है। अन्य सदस्य हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री एम.डी. मल्या, और भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यपालक डॉ. के. रामकृष्णन। उक्त पैनल 30 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा, ताकि बैं किंग लाइसेंस सहित आवश्यक अनुमोदन अक्तूबर, 2013 तक प्राप्त किए जा सकें। पूर्णत: महिला बैंक द्वारा नवम्बर 2013 तक कार्य आरंभ कर दिए जाने की आशा है।

बैंकों द्वारा ऋण चूककर्ताओं और गारंटीदाताओं की तस्वीरें प्रकाशित करने का फैसला

उधारकर्ताओं को उनकी देय राशियों की चुकौती करने पर विवश करने हेतु 'ख्याति और बदनामी' वाली नीति अपनाते हुए बैंकों ने ऋणों के इरादतन चूककर्ताओं की तस्वीरें और नाम एवं पते जैसे विवरण समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का फैसला किया है। इसके अलावा, मूल उधारकर्ताओं के विवरण देने वाली सूचना के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर देय राशियों की चुकौती न किए जाने पर

बैंक इस प्रकार के चूककर्ताओं के गारंटीदाताओं की तस्वीरें, नाम एवं पते भी समाचार पत्रों में प्रकाशित करेंगे। कुछेक बैंकों ने ऐसे उधारकर्ताओं के इलाके में स्थित शाखाओं में भी इसप्रकार के इरादतन ऋण चूककर्ताओं के विवरण प्रमुखता के साथ प्रदर्शित करने का भी निर्णय लिया है।

बैंकों के 10% की सीमा तक पहुंने के कारण ामा प्रमाणपत्रों के निर्गमन में गिरावट

अधिकांश सार्वानिक क्षेत्र के बैंकों के ामा प्रमाणपत्रों से सम्बन्धित 10% की सीमा तक पहुं ााने के परिणामस्वरूप प्राथमिक बाज़ार के निर्गमन लगभग आधे रह गए हैं । बैंकों ने दो और तीन माह के प्रमाणपत्र जारी करके लगभग 1,800 करोड़ जुटाए थे, जो जुटाई गई लगभग 4,000 करोड़ रुपये की रकम से कम है। वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से जमा प्रमाणपत्रों पर अपनी निर्भरता को अपनी कुल जमाराशियों के 10% तक सीमित रखने हेतु कहा था, जबकि थोक जमाराशियों और जमा प्रमाणपत्रों पर संयुक्त सीमा 15% रखी गई थी। मंत्रालय का यह निर्देश बैंकों द्वारा उनके वर्षांत के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु पिछले वित्त वर्ष के अंतिम माह में नकदी के लिए की गई छीना-झपटी के बाद आया। इस वर्ष का दृश्य भिन्न ही है। बढ़े हुए सरकारी व्ययों की पृष्ठभूमि में बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि उल्लेखनीय रूप से घट गई । इससे दो माह और तीन माह वाले जमा प्रमाणपत्रों जैसी अल्पावधिक जमाराशियों की दरों में 25-30 आधार अंकों की कमी लाने में सहायता प्राप्त हुई । व्यापारियों के अनुसार दो और तीन माह वाले जमा प्रमाणपत्रों की दरें, जो लगभग 9.60% थीं, घट कर लगभग 9.25 - 9.30% हो गईं।

कारपोरेट ऋण पुनर्व्यवस्था कक्ष द्वारा ऋण पुनर्व्यवस्था में 105% की वृद्धि

कारपोरेट ऋण पुनर्व्यस्था (CDR) कक्ष द्वारा अप्रैल और फरवरी के बीच बिखरे हुए 64,818 करोड़ रुपये मूल्य के ऋणों को पुनर्व्यस्थित किया गया, जो पिछले वर्ष की 31,601 करोड़ रुपये की संख्या की तुलना में 105% का उछाल है। वर्ष 2011-12 में प्रेषित 67,088 करोड़ रुपये मूल्य वाले 87 मामलों की तुलना में फरवरी तक के 11 महीनों में 61,601 करोड़ रुपये के 117 ऋणों को पुनर्व्यवस्थित करवाया गया।

ामा की तुलना में ऋण अनुपात 78% के अब तक के सर्वोा स्तर पर

प्रणाली में ऋण वृद्धि ामा सांय से अधिक होने का क्रम ाारी रहने के परिणामस्वरूप 22 फरवरी को समाप्त पखवाड़े में जमा की तुलना में ऋण अनुपात पिछले पखवाड़े के 77.6% से बढ़ कर 78.1% के अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया। ऋण वृद्धि में वर्षानुवर्ष 16% का शुंडाकार औसत दर्ज होने

के बावजूद जमाराशियों में अब से एक वर्ष से अधिक समय से धीमी गति से वृद्धि हुई है। 22 फरवरी को समाप्त पखवाड़े में जमाराशियां वर्षानुवर्ष 12.73% की दर से बढ़ कर 65,61,501 करोड़ रुपये हुईं, जबकि वर्ष 2011 के अंत में इस वृद्धि का औसत 18% रहा। एक वर्ष से आा तक (YTD) के आधार पर ऋणों और ामाराशियों में क्रमश: 9% और 7.3% की वृद्धि हुई।

कृषि ऋण की मांग उा बनी रही

इस वर्ष कृषि ऋण की मांग अन्य क्षेत्रों में कमतर मांग परिलक्षित होने के बावजूद स्थिर बनी हुई है। बैंक ऋणों के सेक्टरवार विकास के भारतीय रिज़र्व बैंक के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष में कृषि ऋणों में 19.8% की सुदृढ़ वृद्धि दर परिलक्षित हुई। कुल मिला कर जनवरी, 2013 में खाद्येतर ऋण वृद्धि पिछले वर्ष जनवरी में 15.9% के मुकाबले 14.6% रही। कृषि को छोड़कर सभी प्रमुख क्षेत्रों में पिछले वर्ष की तुलना में ऋण की मांग कमतर रही।

बैंकों को फोटो सहित डेबिट, क्रेडिट कार्ड जारी करने की सलाह दी गई

वित्त राज्य मंत्री श्री नमो नारायण मीणा द्वारा दी गई सूचना के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने चोरी हुए कार्डों का दुरुपयोग किए जाने से बचने के लिए बैंकों को कार्डधारकों के फोटोग्राफ सहित डेबिट, क्रेडिट कार्ड जारी करने की सलाह दी है।

बढ़ते चालू खाते के घाटे के प्रति फिर से चिंता

यद्यपि हाल के दिनों में वृद्धि के मोर्चे पर कुछ हरित (यथा- व्यापारिक मालों के निर्यात में छलांग तथा पूंजी के अन्तर्वाहों में उछाल) अंकुरण दिखाई पड़ते हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक ने चालू खाते के बढ़ते घाटे पर अपनी चिंता पुन: व्यक्त की है और इस अंतर को कम करने हेतु प्रयासों की मांग की है। चालू खाते के बढ़ते घाटे, जिसके इस वित्त वर्ष में 5% के रिकार्ड स्तर पर पहुंच जाने की आशा है, को उन मूल कारणों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है जो भारतीय रिज़र्व बैंक को दरों में और कटौती करने से रोक सकते हैं। "चालू खाते के घाटे और विदेशी मुद्रा में अन्तर्वाहों एवं ब हिर्वाहों के बीच विद्यमान अंतरों के कारण वित्त वर्ष 13 की तीसरी तिमाही में अपेक्षित तीव्र गिरावट की तुलना में 4थी तिमाही में संभाव्य सुधारों के बावजूद जोखिम महत्वपूर्ण बने हुए हैं।" जहां 1ली तिमाही में चालू खाते का घाटा 3.9% रहा, वहीं वह दूसरी तिमाही में एच1 चालू खाते के घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.65% पर पहुंचाते हुए 5.4% के ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तर तक पहुंच गया।

30 बैंक जोखिम-आधारति पर्यवेक्षण अपनाने वाले हैं

30 बड़े बैंकों ने भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित किया है कि वे 1 अप्रैल से नयी एकसमान जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण प्रणाली अपनाने हेतु तैयार हैं। यह प्रणाली उन्हें उनके ोखिमों का यथासमय आधार पर निर्धारण करने में समर्थ बनाएगी। यह वर्तमान में प्रयुक्त होने वाले कैमेल्स ाो,

ासिमें अनुपालन पर आधारित और लेनदेन की जांच वाला दृष्टिकोण अपनाया जाता है, के स्थान पर बैंकिंग प्रणाली की वित्तीय स्थिति की जांच करने के लिए एकसमान कार्यप्रणाली की शुरूआत भी करेगी। नयी प्रणाली भारत में बैंकिंग पर्यवेक्षण को विश्व में प्रालित उत्तम प्रथाओं के अनुरूप लाएगी।

क्रेडिट कार्ड व्यवसाय में उथल-पुथल वाली प्रवृत्ति

ाूकों में महत्वपूर्ण कमी और आय पर आधारित उधार पर संकेन्द्रण के बीा बैंकों को उनके क्रेडिट कार्ड व्यवसाय में अच्छी-खासी वृद्धि दर की अनुभूति हो रही है। जनवरी 2012 के अंत में 8.5% के मुकाबले जनवरी 2013 के अंत में क्रेडिट कार्ड ऋणों में 24.3% की वर्षानुवर्ष वृद्धि परिलक्षित हुई। निरपेक्ष दृष्टि से क्रेडिट कार्ड ऋण एक वर्ष पहले के 20,300 करोड़ रुपये के समक्ष जनवरी 2013 के अंत में 25,200 करोड़ के स्तर पर थे।

बैंकों में ग्राहक शिकायतों में कार्ड शीर्ष स्थान पर

वर्ष 2011-12 के लिए बैंकिंग लोकपाल रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि ऊपर वर्णित अवधि के दौरान कम से कम 14,492 बैंक ग्राहकों ने कार्ड से सम्बन्धित शिकायतें दर्ज कराई थीं। जिनमें से 9,350 शिकायतें केवल एटीएम / डेबिट कार्ड से सम्बन्धित थीं। कार्ड से सम्बन्धित शिकायतों की संख्या पिछले तीन वर्षों में घट कर 2009-10 में लगभग 18,810 रह गई थी।

निधियां जुटाने के लिए बहियां स्वच्छ करें

वित्त मंज्ञालय द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की अनर्जक आस्तियों पर अपने रुख में कठोरता लाने के परिणामस्वरूप बैंकों को सार्वजनिक निधियों का दोहन करने से पहले अपनी बहियों को स्वच्छ करना होगा। मंत्रालय को भय है कि अधिक अनर्जक आस्तियों की परिणति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के, विशेषत: उस समय जब वे 2013-14 से प्रारंभ होने वाले बासेल-III मानदंडों के तहत उच्चतर पूंजी आवश्यकताएं पूरी करने हेतु इक्विटी जुटाने की तैयारी में लगे हो, घटिया मूल्यांकन में होगी। दिसम्बर, 2012 तक जमाराशियों के प्रतिशत के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सकल अनर्जक आस्तियों में एक वर्ष पहले के 3.22% की तुलना में 4.18% की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि पर चिंतित होकर वित्त मंत्रालय ने पिछले छ: वर्षों में अशोध्य ऋणों, बट्टे डाले गए ऋणों की वसूली के विवरण मंगवाए हैं।

विनियामकों के कथन

मुद्रास्फीति -सूचकांकित बॉण्डों से बचत प्रोत्साहित होगी

राजकोषीय और चालू खाते के दोहरे घाटों को कम करने की सरकार की पहलकदमी से भारतीय अर्थव्यवस्था में राजकोषीय जोखिमों में उल्लेखनीय रूप से कमी आएगी। भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. उर्जित पटेल का कहना है कि वित्त वर्ष 2012-13 में प्राप्त किए गए तथा वित्त वर्ष 2013-14

के लिए लक्ष्यित राजकोषीय लक्ष्य सरकारी वित्त के वहनीय पुनर्संतुलन के लिए बुनियाद का कार्य करेंगे। इससे अर्थव्यवस्था में विश्वास पैदा होगा तथा घरेलू एवं विदेशी निवेशों को समर्थन प्राप्त होगा । शीर्ष बैंक ने निवेशकों को सोने से दूर ले जाने के लिए मुद्रास्फीति-सूचकांकित बॉण्ड प्रवर्तित करने के सरकार के निर्णय का भी स्वागत किया है। उक्त योाना को नवोन्मेषकारी बताते हुए डॉ. पटेल ने कहा कि "मुद्रास्फीति-सूाकांकित बॉण्डों से बातकर्ताओं के विकल्प में वृद्धि होगी तथा यह विशेष रूप से उन ोखिम-विमुख निवेशकों के लिए आकर्षक है, जिन्हें आश्वस्त वास्तविक प्रतिलाभ प्राप्त होगा। मुद्रास्फीति-सूचकांकित बॉण्ड घरेलू बचतों को उस सोने से दूर जाने हेतु प्रोत्साहित करेंगे जो अर्थव्यवस्था के लिए व्यापक तौर पर अनुत्पादक है। इससे अर्थव्यवस्था के समक्ष चालू खाते के घाटे वाले जोखिम से निपटने में सहायता प्राप्त होगी, क्योंकि हाल के वर्षों में सोने के उच्च आयात ने चालू खाते के घाटे को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा दिया है।"

भारतीय रिज़र्व बैंक जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण के उपयोग के पक्ष में

भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकों के वित्तीय निष्पादनों पर निगरानी रखने के लिए मौजूदा कैमेल्स दृष्टिकोण के साथ जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण के उपयोग के पक्ष में है। भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री आनंद सिन्हा ने मत व्यक्त किया है कि कैमेल्स दृष्टिकोण का अनुसरण करते समय भी बैंकों का अधिक व्यापक मूल्यांकन प्राप्त करने के लिए जोखिम के वितरण और उसकी दिशा का मूल्यांकन किया ाना ाहिए। कैमेल्स दृष्टिकोण में बैंकों का परीक्षण उनकी पूंाी पर्याप्तता, आस्ति की गुणवत्ता के प्रबन्धन, र्आन, ालनिधि, प्रणालियों एवं नियंत्रणों के सम्बन्ध में किया ाता है तथा एक अंक पत्र (Scorecard) तैयार किया जाता है। यह दृष्टिकोण अतीत के आंकड़ों पर निर्भर करता है, जबकि जोखिम पर्यवेक्षण दृष्टिकोण में अग्रगामी कार्यप्रणालियां शामिल होती हैं।

प्रभावी नीतियां मुद्रास्फीति को रोक सकती हैं

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव का कहना है कि "भारत में मुद्रास्फीति अधिकांशतया आपूर्ति से सम्बन्धित बाधाओं के कारण है, जिसे नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से सुधारा जा सकता है। स्थिर उच्च आर्थिक वृद्धि की हमारी सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षा की सफलता न्यून एवं स्थिर मुद्रास्फीति में निहित है। सुविज्ञ विकल्प अपनाने और वृद्धि में अंशदान करने में निवेशकों और उपभोक्ताओं की सहायता करने के लिए मूल्य स्थिरता आवश्यक है। पिछले तीन वर्षों में भारत में मुद्रास्फीति की औसत दर वृद्धि की ओर झुकी रही है, किन्तु यह प्रवृत्ति भारतीय रिज़र्व बैंक को अपने मुद्रास्फीति से सम्बन्धित ध्येय को संशोधित करने हेतु उसके समक्ष न तो आवश्यक और न ही पर्याप्त स्थिति प्रस्तुत करती है। मुद्रास्फीति के लिए एक नया मानक स्वीकार

किए जाने के लिए न केवल सैद्धांतिक अथवा अनुभवजन्य समर्थन की आवश्यकता होगी, अपितु वह आपूर्ति सम्बन्धी बाधाओं से निपटने के लिए नीतिगत निष्क्रियता का नैतिक संकट भी उपस्थित कर देती है।"

नीति- समिति योजना के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को अधिक स्वतंत्रता की जरूरत

11

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव ने कहा है कि शीर्ष बैंक द्वारा मौद्रिक नीति- समिति वाला ढांचा अपनाए जाने से पहले उसे अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की जरूरत होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक कुछेक ऐसे महत्वपूर्ण केन्द्रीय बैंकों में से एक है, जिनमें मौद्रिक नीति से सम्बन्धित निर्णय लेने का अधिकार समिति की बजाय गवर्नर में निहित है। जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक सांविधिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, वहीं व्यवहार में मौद्रिक नीति निर्धारित करने में उसे व्यापक स्वतंत्रता उपलब्ध है। डॉ. सुब्बाराव मौद्रिक नीति - समिति वाले ढांचे की दिशा में आगे बढ़ने के लिए केन्द्रीय बैंक की स्वतंत्रता को एक उपयुक्त पूर्ववर्ती (Precursor) के रूप में देखते हैं।

बीमा

बैंक बहुलित बीमा फर्मों की पॉलिसियां बेच सकते हैं

वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने घोषणा की है कि बैंक बहुलित कम्पनियों के बीमा उत्पादों को बेचने के लिए दलालों के रूप में कार्य करेंगे। वर्तमान में, बैंक एक जीवन और एक सामान्य बीमा और एकल आधार वाले स्वास्थ्य बीमाकर्ता के उत्पाद बेच सकते हैं। हालांकि, अब बैंकों द्वारा एकत्रित किए गए अपने ग्राहक को जानिए से सम्बन्धित विवरण बीमा पॅलिसी खरीदने के लिए पर्याप्त होंगे और अब समूह बीमा उत्पाद स्वयं सहायता समूहों, घरेलू कामगार संघों आदि जैसे समूहों को प्रदान किए जाएंगे।

65 वर्ष की आयु तक नये स्वास्थ्य बीमा से इनकार नहीं

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने इस खंड के लिए विविध प्रकार के नये नियमों को अंतिम रूप दिया तथा उन्हें राजपत्रित किया है। इनमें सामान्य बीमाकर्ताओं द्वारा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों (IPOs), स्वास्थ्य बीमा खण्ड में अन्य पक्ष के प्रशासकों (TPAs) के सम्बन्द में एक तथा स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा का भी समावेश है। इन नियमों के अनुसार अन्य बातों के साथ ही 65 वर्ष तक की आयु तक प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता और विदेश यात्रा के मामले को छोड़कर आयु के कारण नवीकरण से इनकार नहीं किया जा सकता।

पारंपरिक उत्पादों के नवीयन हेतु इर्डा के नये दिशानिर्देश

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने पारंपरिक उत्पादों के सम्बन्ध में कमीशन, बीमित न्यूनतम रकम और गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य को सीमित करने हेतु अंतिम दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। विनियामक ने बीमा कम्पनियों से उन पॉलिसी धारकों को प्रतिलाभ की दर बताने के लिए भी कहा हे जिन्हें सूचकांक सम्बद्ध उत्पादों द्वारा अभिशासित प्रतिलाभों का पता लगाने में कठिनाई होती है। नये दिशानिर्दशों में गैर-सहभागी सूचकांक सम्बद्ध उत्पादों को यूनिट-सम्बद्ध बीमा पॉलिसियों के

समान माना गया है और व्यापक तौर पर यूनिट-सम्बद्ध बीमा पॉलिसी ढांचे को अपनाया जाएगा। गैर-सहभागी योजना निधि के लाभ में सहभागिता नहीं करती तथा लाभों को प्रारंभ में ही सुस्पष्ट रुप से परिभाषित कर दिया जाता है।

यूनिट-सम्बद्ध बीमा उत्पादों के लिए मानदंड जारी

अब पॉलिसी धारकों की बीमा उत्पादों का बेहतर रीति से मूल्यांकन एवं तुलना करा लेने में सहायता करने हेतु स्वतंत्र रेटिंग एजेन्सी को बीमा कम्पनियों की यूनिट-सम्बद्ध निधियों का मूल्यांकन करने की अनुमति होगी। उक्त सूचना पॉलिसी धारकों को परिचालनात्मक प्रथाओं, निधि प्रबन्धन की गुणवत्ता तथा जीवन बीमाकर्ताओं की संगठनात्मक शक्ति के सम्बन्ध में स्पष्टता प्रदान करेगी। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने सम्बद्ध बीमा उत्पाद के व्यापक दिशानिर्देशों को राजपत्र में अधिसूचित कर दिया है। बीमाकर्ताओं को नये दिशानिर्देशों का अनुपालन करने हेतु (समूह उत्पादों के मामले में) 30 जून तक का और (वैयक्तिक उत्पादों के मामले में) 30 सितम्बर तक का समय दिया गया है।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियों में 2 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि

वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम द्वारा विदेशी निवेशकों को मारीशस मार्ग का उपयोग करते हुए निरंतर कर लाभ का आश्वासन दिए जाने के बाद भारत की विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियों में 15 मार्च, 2013 को समाप्त सप्ताह में 2 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई तथा वह बढ़कर 292,317 बिलियन अमरीकी डालर हो गई।

अप्रैल 2013 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों लिबोर / अदला-बदली दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक के लिए लिबोर / अदला-बदली			
	लिबोर	अदला-	

		बदली			
मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष

अमरीकी डालर	0.73150	0.427	0.533	0.728	0.948
जीबीपी	0.90938	0.6319	0.6876	0.7950	0.9737
यूरो	0.42786	0.515	0.616	0. 762	0.925
जापानी येन	0.45071	0.235	0.239	0.259	0.293
कनाडाई डालर	1.79350	1.325	1.425	1.552	1.679
आस्ट्रेलियाई डालर	3.57500	3.105	3.250	3.455	3.578
स्विस फ्रैंक	0.25600	0.113	0.193	0.314	0.463
डैनिश क्रोन	0.69500	0.7025	0.7950	0.9310	1.100
न्यूजीलैंड डालर	2.69000	2.880	3.068	3.245	3.380
स्वीडिश क्रोन	1.71750	1.432	1.555	1.674	1.904
सिंगापुर डालर	0.38500	0.445	0.560	0.780	0.895
हांगकांग डालर	0.42000	0.470	0.570	0.730	0.930
एमवाईआर	3.24000	3.250	3.320	3.380	3.480

स्रोत : भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां

मद	**22 मार्च, 2013 के दिन**	**22 मार्च, 2013 के दिन**
	बिलियन् रुपये	मिलियन अमरीकी डालर
	1	2
कुल प्रारक्षित निधियां	15, 925, 3	2 93,366 8
क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	14, 149.7	260,415. 3
ख) सोना	1, 413, 8	26, 292. 3
ग) विशेष आहरण अधिकार	235, 9	4, 341.9
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	125.9	2, 317.3

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

उत्पाद एवं गंठजोड़

14

संगठन	जिस संगठन के साथ गंठजोड़ हुआ	उद्देश्य
येस बैंक	पर्यटन मंत्रालय	अतुल्य भारत यात्रा कार्ड - भारत में यात्रा को नकदी रहित और अड़चन रहित अनुभव बनाना
भारतीय रिज़र्व बैंक	रॉयल मॉनेटरी अथारिटी ऑफ भूटान	100 मिलियन डालर या उसकी समतुल्य कई एक श्रृखलाओं में डालर, यूरो अथवा रुपया आहरित करने के लिए पहला मुद्रा अदला-बदली करार
केनरा बैंक	राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC)	उड़ान के अधीन जम्मू एवं कश्मीर के स्नातक बेरोज़गार युवकों के कौशल विकास एवं उनकी भर्ती के लिए
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)	दि ऑटोमोटिव काम्पोनेंट मैन्युफैक्चररर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया(ACMA)	उसके सदस्यों की ऋण तक सरल पहुंच के लिए। पूंजीगत व्यय और कार्यशील पूंजी, दोनों के लिए 670 सदस्य वि निर्माताओं को साख एवं ऋण सुगम बनाएगा।
दोहा बैंक	इंडियाबुल्स रि यल इस्टेट लि मिटेड	अपने अनिवासी भारतीय ग्राहकों को भारत में सम्पत्तियों के सम्बन्ध में अनन्य सौदे प्रदान करना ।

नयी नियुक्तियां

नाम	पदनाम / संगठन
श्री बी. श्रीराम	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के प्रबन्ध निदेशक

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (क्रमश:)

दबाव-परीक्षण पर चर्चा को जारी रखते हुए हम तीसरे सिद्धांत को समझेंगे।

3. दबाव-परीक्षण कार्यक्रमों को सम्पूर्ण संगठन के विचारों को ध्यान में रखना चाहिए तथा उनमें पि रप्रेक्ष्यों एवं तकनीकों की श्रृंखलाओं का समावेश होना चाहिए।

प्रासंगिक दबाव की घटनाओं की पहचान, सुदृढ़ मॉडेलिंग दृष्टिकोणों के प्रवर्तन और दबाव-परीक्षण प रिणामों के उपयुक्त उपयोग, प्रत्येक के लिए किसी बैंक में जोखिम नियंत्रकों, अर्थशास्त्रियों, व्यवसाय प्रबन्धकों और व्यापारियों जैसे विभिन्न वरिष्ठ विशेषज्ञों के बीच सहयोग की आवश्यकता होती है। दबाव-परीक्षण कार्यक्रम को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी सम्बन्धित विशेषज्ञों के

अभिमतों को विशेष रूप से फर्म-व्यापी दबाव-परीक्षणों में ध्यान में रखा जाए। दबाव-परीक्षण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के उत्तरदायित्व वाली इकाई को इन विशेषज्ञों के बीच यथोचित संवाद का आयोजन करना चाहिए, उनके अभिमतों को चुनौती देनी चाहिए, सुसंगतता के लिए उनकी (अन्य सुसंगत दबाव-परीक्षणों से) जांच करनी चाहिए तथा उपयोगिता, परिशुद्धता, व्यापकता और व्यवहार्यता के बीच यथोचित संतुलन सुनिश्चित करते हुए दबाव-परीक्षणों की डिज़ाइन और उसके कार्यान्वयन के बारे में निर्णय लेना चाहिए।

बैंकों को उनके दबाव-परीक्षण कार्यक्रमों में व्यापक व्याप्ति लाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुविध पि रप्रेक्ष्यों एवं तकनीकों की श्रृंखलाओं का उपयोग करना चाहिए। इनमें मॉडेलों के उपयोग को समर्थन प्रदान करने और उन्हें पूरक बनाने हेतु तथा दबाव-परीक्षण को उन क्षेत्रों तक फैलाने के लिए
मात्रात्मक एवं गुणात्मक तकनीकों का समावेश होता है, जिनमें प्रभावी जोखिम प्रबन्धन के लिए निर्णयन के अपेक्षाकृत अधिक उपयोग की जरूरत पड़ती है। दबाव-परीक्षणों को किसी विशिष्ट जोखि खम कारक में हुए परिवर्तनों के आधार पर सामान्य संवेदनशीलता विश्लेषण से लेकर ऐसे अधिक ज टिल दबाव-परीक्षणों तक व्याप्त होना चाहिए जो दबाव की घटनाओं के आधार पर जोखिम प्रेरक तत्वों के बीच अन्योन्य क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए पोर्टफोलियो का पुनर्मूल्यन करते हैं। कुछेक दबाव-परीक्षण नियमित अंतरालों पर संचालित किए जाने चाहिए, जबकि दबाव-परीक्षण कार्यक्रमों को तदर्थ दबाव-परीक्षण करने की संभावना की भी अनुमति देनी चाहिए।

संवेदनशीलता विश्लेषण का अभीष्ट सामान्यतया मात्रात्मक दृष्टिकोणों से निकले परिणामों का उस समय मूल्यांकन करना होता है, जब कुछेक सूचनाओं और मापदंडों को दबावग्रस्त या आघात पहुंचाया जाता है। अधिकांश मामलों में संवेदनशीलता विश्लेषण में उन परिवर्तनों को किसी अन्तर्नि हित घटना या वास्तविक दुनिया के परिणामों से सम्बद्ध किए बिना सूचनाओं या मापदंडों को बदलने से सम्बन्धित होते हैं। उदाहरण के लिए कोई संवेदनशीलता परीक्षण इक्विटी की कीमतों में भिन्न-भिन्न (जैसे कि 10%, 20%, 30%) गिरावटों या ब्याज दरों में (जैसे कि 100, 200, 300 आधार अंकों की) वृद्धियों की श्रेणी के प्रभाव का पता लगा सकता है। जहां यह दबाव के पारंपरिक अव धियों से चरम मूल्यों को निकालने में सहायक होता है, वहीं संवेदनशीलता विश्लेषण में यह सुनिश्चित करने के लिए कि संभावनाओं की एक व्यापक श्रेणी का समावेश किया गया है, परिकल्पनात्मक चरम मूल्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए। कुछेक मामलों में यह उसके साथ ही कतिपय कारकों के परिदृश्य विश्लेषण करने में सहायक हो सकता है, क्योंकि कारकों का अलग-अलग स्तर पर केवल परीक्षण करने से (विशेष रूप से उस अन्योन्य क्रिया के जटिल होने तथा सहज बोधनीय रूप से स्पष्ट न होने पर) उनकी संभाव्य अन्योन्य क्रियाओं का पता नहीं चल सकता। उदाहरण के लिए परिदृश्य चूक की संभाव्यताओं में अचानक उठे शूलों और किसी ऋण पूंजी मॉडेल की निर्भरता के मापदंडों में सहवर्ती परिवर्तनों से उपजी ऋण जोखिम पूंजी आवश्यकताओं पर सम्मिलित प्रभाव का मूल्यांकन कर सकते हैं।

संवेदनशीलता और परिदृश्य विश्लेषण में यह जानने में सहायता करने का अतिरिक्त लाभ निहित होता है कि मात्रात्मक दृष्टिकोण मूलत: उद्दिष्ट रूप में कार्य कर रहे हैं या नहीं। उदाहरण के लिए इस मान्यता की जांच की जा सकती है कि चरम सूचनाओं का उपयोग किए जाने पर सम्बन्ध रैखिक बने रहते हैं। विश्लेषण के परिणामों के यह दर्शाने पर कि कोई विशिष्ट मॉडेल अस्थिर है या फिर

वह मूल रूप से यथा-अभीष्ट चरम सूचनाओं के साथ कार्य नहीं करता, तो प्रबन्धन को मॉडेल, , कुछेक मापदंडों को आशोधित करने पर अथवा कम से कम मॉडेल के आउटपुट की परिशुद्धता पर कम विश्वास करने पर पुनर्विचार करना चाहिए। अंत में संवेदनशीलता और परिदृश्य विश्लेषण निय मित रूप से (केवल मॉडेल के विकास के दौरान ही नहीं) किए जाने चाहिए, क्योंकि माडेलों में खराबी आ सकती है और समय बीतने के साथ चरों के बीच सम्बन्ध बदल सकते हैं।
(स्रोत : अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक)

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

आनुक्रमिक भुगतान बंधक

स्थिर दर वाले बंधक का एक ऐसा प्रकार जिसमें भुगतान प्रारंभिक रूप से कम आधार वाले स्तर से क्रमिक रूप से बढ़ कर वांछित, अंतिम स्तर तक पहुंच जाता है। विशिष्ट रूप से यह भुगतान उनके प्रारंभिक आधार वाले भुगतान की रकम से 7-12% वार्षिक की दर से संपूर्ण भुगतान तक पहुंचने तक बढ़ेगा। आनुक्रमिक भुगतान बंधक में क्रेता को पात्र बनाने के लिए केवल न्यून प्रारंभिक दर का उपयोग किया जाता है, जो ऐसे अनेक लोगों, जो अन्यथा किसी बंधक को मकान का मालिक बनने की अनुमति नहीं दे सकते, को अनुमति देता है। इस प्रकार की बंधक भुगतान प्रणाली युवा मकान-मा लिकों के लिए इष्टतम हो सकती है, क्योंकि उनकी आय के स्तर उच्चतर बंधक भुगतानों को पूरा करने के लिए क्रमिक रूप से बढ़ते हैं।

शब्दावली

ईएमवी (यूरोपे, मास्टर कार्ड और वीसा)

ईएमवी यूरोपे, मास्टर कार्ड और वीसा - एकीकृत परिपथ (सर्किट) कार्ड (आईसी कार्डों या "चिप कार्डों) के अंतर-परिचालन के वैश्विक मानक का संक्षिप्त रूप है और आईसी कार्ड बिक्री केन्द्र (PoS) टर्मिनलों तथा स्वचालित टेलर मशीनों (ATMs) पर क्रेडिट और डेबिट कार्ड लेनदेनों को अधिप्रमा णित करने में सक्षम होता है। यह यूरोपे, मास्टरकार्ड और वीसा के बीच सुरक्षा और वैश्विक अंतर-प रिचालनीयता को सुनिश्चित करने का एक संयुक्त प्रयास है, ताकि वीसा और मास्टरकार्ड कार्डों को प्रत्येक स्थान पर स्वीकार किए जाने का क्रम जारी रह सके। यूरोपे, मास्टर कार्ड और वीसा मानक

आईसी कार्डों और आईसी कार्ड संसाधन उपकरणों के बीच वित्तीय लेनदेनों के लिए भौतिक, इलेक्ट्रिकल, डाटा एवं अनुप्रयोग के स्तरों पर अन्योन्य क्रिया को परिभाषित करते हैं।

संस्थान की गतिविधियां

17

मार्च, 2013 माह के दौरान पूरी की गई प्रशिक्षण की गतिविधियां

क्रम सं.	कार्यक्रम	दिनांक
1	ऋण मूल्यांकन (औद्योगिक एवं वाणिज्यिक अग्रिम)	25 फरवरी से 1 मार्च 2013 तक
2	आवास वित्त पर कार्यक्रम	4 से 6 मार्च, 2013 तक

अप्रैल, 2013 2013 माह के लिए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम सं.	कार्यक्रम	तिथि
1	अपने ग्राहक को जानिए / धन शोधन निवारण / आतंकवाद का मुकाबला पर 2रा कार्यक्रम	15 से 17 अप्रैल, 2013 तक
2	बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स और राष्ट्रीय बैंक प्रबन्धन संस्थान द्वारा बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद में संयुक्त रूप से संचालित 1ला कार्यपालक विकास कार्यक्रम (BEP)	22 से 27 अप्रैल 2013 तक
3	सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा और साइबर अपराधों पर 2री एक-दिवसीय कार्यशाला	22 अप्रैल, 2013

संस्थान समाचार

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री

संस्थान ने विविध परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य (मास्टर) परिपत्रों से संग्रहीत अतिरिक्त अध्ययन सामग्री अपने पोर्टल पर डाल रखी है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in. देखें।

---

* भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास आरएनआई संख्या : 69228 / 98 के अधीन पंजीकृत * डाक पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / दक्षिण -42 / 2010 -12 * प्रत्येक महीने की 25वीं को प्रकाशित * मुंबई पत्रिका चैनल छंटाई कार्यालय मुंबई - 1 पर प्रेषित * प्रेषण की तिथि प्रत्येक महीने की 25वीं से 30वीं तारीख

जेएआईआईबी /डीबीएण्डएफ और सीएआईआईबी के लिए वेब कक्षाएं और ई-शिक्षण

संस्थान ने जेएआईआईबी /डीबीएण्डएफ और सीएआईआईबी के सभी अभ्यर्थियों के लिए अपनी वेब कक्षाओं और ई-शिक्षण की सुविधा जारी रखी है। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in. देखें।

ई-मेल के माध्यम से आईआईबीएफ विजन

संस्थान ने आईआईबीएफ - विज़न उसके पास पंजीकृत ई-मेल पतों पर ई-मेल द्वारा भेजना आरंभ कर दिया है। जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते संस्थान के पास पंजीकृत नहीं करा रखे हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल पते यथाशीघ्र पंजीकृत करा लें। आईआईबीएफ - विज़न संस्थान के पोर्टल में डाउनलोड करने हेतु भी उपलब्ध है।

जेएआईआईबी /डीबीएण्डएफ और सीएआईआईबी के लिए संपर्क कक्षाएं

संस्थान ने जेएआईआईबी /डीबीएण्डएफ और सीएआईआईबी पाठ्यक्रमों के लिए संपर्क कक्षाओं की घोषणा की है। संपर्क कक्षाओं के कार्यक्रम वेसाइट पर अपलोड किए गए हैं। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in. देखें।

बाज़ार की खबरें

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

87
82
77
72
67
62
57
52

01/03/13 04/03/13 07/03/13 13/03/13 14/03/13 18/03/13 22/03/13 25/03/13 28/03/13

अमरीकी डालर यूरो 100 जापानी येन पौंड स्टर्लिंग

स्त्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

19

- 4 को पिछले दो माह में सबसे कमजोर सत्र में रुपया प्रति डालर 54.22 के अंत: दिवसीय उच्च स्तर पर पहुंच गया। मुद्रा व्यापारी रुपये के लगभग 2% गिर कर और कमजोर पड़ कर प्रति डालर 56 पर आने की आशा करते हैं, क्योंकि स्थानीय मुद्रा इक्विटी बाज़ारों में वह कमजोर मनोभावों पर मूल रूप से दबाव के अधीन है।
- 6 को रुपये में मज़बूती आई, क्योंकि वैश्विक जोखिम बढ़ जाने से एशियाई मुद्राओं और शेयरों में तेजी आई, किन्तु तेल कम्पनियों से डालर की दुराग्रही मांग ने तीव्र बढ़ोतरी रोक दी। रुपया 20 पैसे बढ़ा और प्रति डालर 54.72 पर बंद हुआ।
- रुपया 11 पैसे गिर कर प्रति डालर 54.31 पर बंद हुआ। इसके पूर्व दो सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद 13 वीं को मुद्रास्फीति के आंकड़ों के घरेलू शेयरों को प्रभावित करने की चेतावनी के तौर पर रुपया लुढ़क गया, जबकि सरकार द्वारा संचालित बैंकों को डालर खरीदते देखा गया, जिसका कारण व्यापारियों ने सरकार की खरीद आवश्यकताओं को बताया।
- 25 वीं को रुपया 16 पैसे बढ़ कर 54.18 प्रति डालर पर बंद हुआ। ऋण बाज़ार में विदेशी निवेशों पर प्रतिबंध और मनोभावों के सम्बन्ध में वैश्विक जोखिम कम करने की सरकारी मुहिम द्वारा प्रोत्साहित हो कर 25वीं को रुपये में मज़बूती आई, किन्तु लाभ राजनीतिक अस्थिरता की चिंताओं से जुड़ गए।
- माह के दौरान स्टर्लिंग, यूरो और जापानी येन जैसी अन्य मुद्राओं के समक्ष रुपये के व्यवहार में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ।

भारित औसत मांग दरें

8.10
7.90
7.70
7.50
7.30
7.10
6.90
6.70
6.50

01/03/13 02/03/13 06/03/13 11/03/13 12/03/13 15/03/13 20/03/13 21/03/13

स्त्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, मार्च, 2012

- मांग दरें व्यापक तौर पर 7.7% और 7.9 % के चीच श्रेणीबद्ध बनी रहीं।
- 2 मार्च को प्रचुर चलनिधि के बीच मांग दरें 6.7& के न्यून स्तर पर पहुंच गईं।

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

20

19900
19700
19500
19300
19100
18900
18700
18500

01/03/13 05/03/13 08/03/13 13/03/13 15/03/13 19/03/13 21/03/13 25/03/13 26/03/13 28/03/13

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

डॉ. आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, डॉ. आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्सियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डॉ. आर. भास्करन

सेवा में
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्सियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)
मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.

वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न अप्रैल, 2013